



हरिभूमि

बजट भूमि

मोदी की गारंटी वाला बजट

समाचार ही नहीं, विचार भी

छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, हरियाणा व दिल्ली से एक साथ प्रकाशित



बजट में प्रमुख क्षेत्रों को क्या मिला	ग्रामीण विकास 1.77 लाख करोड़ का बजट अगले पांच साल में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में और दो करोड़ मकान बनाए जाएंगे।	महिला 26 हजार करोड़ का बजट महिलाओं के लिए सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन के लिए विभिन्न सरकारी पहल।	रक्षा 6.21 लाख करोड़ रुपए रक्षा प्रयोजनों के लिए गहन प्रौद्योगिकियों को मजबूत बनाने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने योजना शुरू।	रेल 2.55 लाख करोड़ रुपए तीन नए बड़े रेल कॉरिडोर, इनमें पोर्ट कनेक्टिविटी, एनर्जी, मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर शामिल।
--	---	--	---	--

GYAN

थीम पर बजट

गरीब

गरीबों के घर का सपना होगा पूरा

कोविड की चुनौती के बावजूद मोदी सरकार ने गरीबों को घर मुहैया कराया। केंद्र सरकार का दावा है कि 3 करोड़ घर के लक्ष्य को बनाने के करीब हैं। 2 करोड़ और घर अगले 5 साल में बनेंगे। छत के ऊपर सोलर एनर्जी के लिए 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगेंगे। सौर प्रणाली वाले एक करोड़ लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी।

युवा

स्टार्टअप्स के लिए एक और मौका

बजट में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ का फंड बनाने की घोषणा की गई है, बजट में स्टार्टअप को मिलने वाले टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। इसमें राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखते हुए पूंजीगत व्यय को 11 लाख 11 हजार 111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है।

अन्नदाता

नैनो डीएपी का अब विस्तार पूरे देश में

नैनो डीएपी का विस्तार पूरे देश में किया जाएगा। तिलहन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यनीति तैयार की जाएगी। डेरी किसानों की सहायता के लिए व्यापक कार्यक्रम बनेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम किसान संपदा से 38 लाख किसानों को फायदा हुआ है।

नारी

3 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य

2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य देखभाल के दायरे में सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लाया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने मुफ्त में टीकाकरण अभियान चलाने की योजना है।

सरकार का आय-व्यय का ब्योरा



कहां से आता है	रुपया कहां जाता है		
कंपनी कर	17 पैसा	केंद्रीय क्षेत्र की योजना	16 पैसे
आय कर	19 पैसा	ब्याज भुगतान	20 पैसे
सीमा शुल्क	4 पैसा	रक्षा	8 पैसे
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	5 पैसा	सखिडी	6 पैसे
जीएसटी एवं अन्य कर	18 पैसा	वित्त आयोग और अन्य अंतरण	8 पैसे
गैर-कर प्राप्ति	7 पैसा	करों और शुल्कों	20 पैसे
गैर-कर पूंजी प्राप्ति	1 पैसा	में राज्य को हिस्सा	
उधार और अन्य देयताएं	28 पैसा	पेंशन	4 पैसे
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	8 पैसे	अन्य व्यय	9 पैसे

● बजट ... भीतर भी देखें

इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, छोटे शहरों को जोड़ने 517 नए रूट पर 'यूडीएन' स्कीम

सीता का राम राम...

3 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति

टैक्स छेड़ा नहीं, भरोसा तोड़ा नहीं

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट गुरुवार को पेश कर दिया। सीतारमण ने कोई लोक लुभावन घोषणा नहीं की है। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट एक साल के लिए बढ़ा दी है। अगले पांच सालों में 2 करोड़ नए घर बनाने का प्रस्ताव दिया है। इनमें 70 फीसदी घरों का मालिकाना हक महिलाओं को दिया जाएगा। आयकर दाताओं को कोई राहत नहीं दी गई है। इससे मिडिल क्लास खासकर नौकरी-पेशा लोग मायूस हुए हैं।



बजट-2024-25 प्रोटी की ग्यारंटी सबका साथ सबका विकास

बंदे भारत एक्सप्रेस - 2024

56 मिनट में रखी अपनी बात, सदन में जय श्रीराम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में अपना लगातार छठा बजट पेश किया और 56 मिनट में अपना बजट भाषण समाप्त किया जो उनका अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण है। फिरोजी रंग की कढ़ाई वाली कांथा सिल्क की साड़ी पहनकर संसद पहुंची सीतारमण के भाषण के दौरान लोकसभा में सत्ता पक्ष के सदस्य उनकी घोषणाओं और टिप्पणियों पर बीच-बीच में मेजें थपथपाते देखे गए। जब उन्होंने कहा कि हमारी सरकार



जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सबसे ज्यादा

देर तक मेजें थपथपाईं। विपक्षी सदस्यों ने भी वित्त मंत्री का बजट भाषण पूरे ध्यान से सुना। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद उनकी सरकार के सत्ता में लौटने संबंधी कथन पर विपक्ष की ओर से कुछ विरोध के स्वर सुनाई दिए। इससे पहले आज पूर्वाह्न 11 बजे बजट भाषण शुरू होने से पहले जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा कक्ष में पहुंचे तो भाजपा के सदस्यों ने 'भारत माता की जय', 'जय श्रीराम' और 'जय सियाराम' के नारे लगाए।

जुबानी तीर

पीएम मोदी बोले

विकसित राष्ट्र बनाने की गारंटी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अंतरिम आम बजट समावेशी और नवोन्मेषी होने के साथ ही देश के मविध्य के निर्माण का बजट है। वीडियो संदेश में पीएम मोदी कहा कि यह बजट 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। उन्होंने कहा, आज का ये बजट समावेशी और नवोन्मेषी बजट है।

समावेशी विकास का बजट

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक पूर्ण विकसित भारत का आह्वान किया है। इस आह्वान को साकार करने की दिशा में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। यह बजट देश के समावेशी विकास का बजट है। उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है।

जनता को दिया धोखा

केंद्रीय बजट पर छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट, कर्ज में डुबोने वाला दिशाहीन, खोखला बजट है। नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत ने कहा कि, देश पर बढ़ता कर्ज मोदी सरकार की गलत नीतियों की देन है।

कांग्रेस ने कहा

यह सरकार का 'विदाई बजट'

विपक्षी दलों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश अंतरिम बजट को निराशाजनक और सरकार का 'विदाई बजट' करार दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा, बजट भाषण बहुत छोटा और निराशाजनक था। बहुत अधिक बयानबाजी थी। कई मुद्दों को छुआ नहीं गया। बेरोजगारी जैसे मुद्दे का उल्लेख ही नहीं किया गया।

प्रमुख घोषणाएं

- सर्वाइकल कैंसर को रोकने टीका मुफ्त**

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में भी अंतरिम बजट में अहम घोषणा की गई है, जिसके तहत 9-14 साल की बच्चियों में सर्वाइकल कैंसर के रोकथाम के लिए मुफ्त में वैक्सीन लगाने की भी योजना है।
- वंदेभारत स्टैंडर्ड के 40 हजार कोच**

रेलवे के 40 हजार डिब्बे वंदे भारत के स्तर के बनेंगे। इसके अलावा इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी एक बड़ी घोषणा की गई। फ्रंट कॉरिडोर यानी माल ढोने के लिए बनाए जा रहे रेलवे कॉरिडोर के अलावा तीन और रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे।
- टैक्स में नोटिस की वापसी**

इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं मिली है। 1962 से 2010 तक के 25 हजार रुपये तक की और वर्ष 2011 से 2015 तक के 10 हजार रुपए की बकाया टैक्स डिमांड को माफ किया जाएगा। अगर किसी के पास 25 हजार रुपए तक का डायरेक्ट टैक्स बकाया है तो उसे नहीं देना होगा।
- देश का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वर्ल्ड क्लास**

देश का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंफ्रास्ट्रक्चर बजट में 11.1 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान करते हुए इसे बढ़ाकर 11.11,111 करोड़ रुपए कर दिया है, जो कि जीडीपी का 3.4 फीसदी है।

फायदा

- बाजार में मिलने वाली टीके की कीमत फिलहाल 2,500-3,300 रुपए प्रति डोज है। यह मुफ्त में मिलेगी।
- रेल यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर देश के प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ेगा।
- टैक्स डिमांड माफ होने से 25 हजार रुपए का लाभ बकायादारों को होगा। नोटिस वापस लेने से राहत मिलेगी।
- देश का तेजी से विकास होगा। सड़क मार्ग बनेंगे। एयरपोर्ट का विकास होगा। रेलवे कॉरिडोर बनने से ट्रांसपोर्टेशन में सुविधा बढ़ेगी।

पारखियों की नजर में बजट



प्रो. मनीषा दुबे एचओडी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर

समावेशी विकास का केंद्रीय..



प्रो. मोहम्मद शमीम वाणिज्य विभाग अलीगढ़ मुस्लिम विवि

ग्रामीण क्षेत्रों का विकास



प्रो. जीसी त्रिपाठी प्राध्यापक अर्थशास्त्र इलाहाबाद विवि,

राष्ट्रीय शिक्षा नीति ...



प्रो. आरएस मीणा वाणिज्य संकाय, बनारस हिंदू विवि, वाराणसी

तकनीक-प्रेमी युवाओं ...



महेश दुबे हास्य कवि मुंबई

वित्त मंत्री तो घोषणाएं..



सुदीप भोला हास्य कवि, मुंबई

ऐसी दरकार तुम्हई ...



अंतरिम बजट 2024

लक्ष्य 2024



हरिभूमि

रायपुर, शुक्रवार 2 फरवरी 2024

सोशल मीडिया



haribhoomi.com

➤ बजट पर मीठी-मीठी पारिवारिक चर्चा - हमको क्या मिला?



➤ बजट अच्छा है... नहीं-नहीं बजट में ये भी होना था.. बहस में बजट



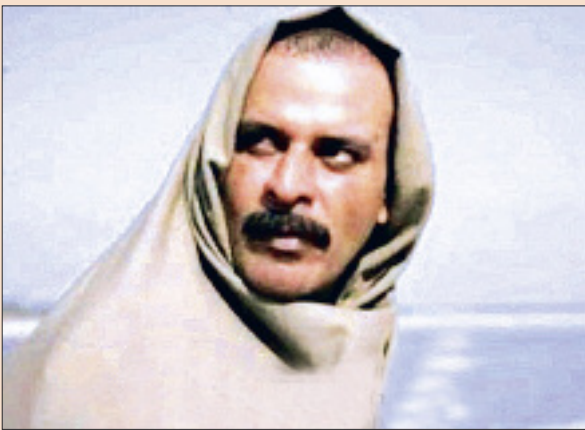
➤ फिल्म 'बाहुबली' से... अपने लिए बजट में क्या, इसकी ऐसी उत्सुकता



➤ ठीक है भाई... जैसा चल रहा है चलने दें... क्यों उलझ रहे हैं?



➤ लगता है कि अब मुझे अर्थशास्त्री बनना ही पड़ेगा तभी समझूंगा.....



सैंस ऑफ ह्यूमर... तोहफा तोहफा... लाया... लाया

लोगों ने कुछ यूं बयां किया हाल-ए-दिल



वि त्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। आम चुनाव से कुछ ही महीने पहले पेश हुआ ये अंतरिम बजट था। मोदी सरकार का दावा है कि अगले तीन साल में वह देश को दुनिया को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देगी। इस बीच सोशल मीडिया पर लोग मीम्स के जरिए अपना हाल-ए-दिल बयां कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला

सीतारमण ने जैसे ही 1 फरवरी को संसद में अंतरिम बजट 2024 पेश किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खासकर 'एक्स' पर मीम्स की बाजार शुरू हो गई। बजट भाषण के बीच इंटरनेट पर कई वर्ग मजेदार मीम्स बनाने में बिजी थे, क्योंकि हर कोई सांसें थामकर सरकार की घोषणाओं का इंतजार कर रहा था। इस दौरान लोगों में अगर किसी चीज को लेकर बेसब्री

थी, तो वो थी इनकम टैक्स स्लैब। लेकिन, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं हो सका। बजट पर सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म से मीम्स शेयर हो रहे हैं। दिनभर ये मीम्स शेयर होते रहे। जिन्हें 'हरिभूमि' इस अंक में प्रकाशित कर रहा है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक व्यंग्यात्मक और मजेदार दृष्टि पाठकों तक पहुंचाना है।

ये है सरकार की नई यात्रा...

सोशल मीडिया पर... उधर 'भारत जोड़ो' इधर 'मध्यम वर्ग जोड़ो' चल पड़ा जोरदार अभियान



गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इधर बजट पेश किया और उधर सोशल मीडिया पर कई रोचक और हास्यव्यंग्य समेटे मीम्स टूट करने लगे। जिसमें से एक मीम्स भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी खूब शेयर किया गया। जिसमें सांकेतिक तौर बताया गया है कि वित्त मंत्री ने मध्यमवर्ग का ख्याल रखते हुए कई तरह की घोषणाएं की हैं। चूंकि, देश में बहुत बड़ा वर्ग मध्यम वर्ग से है। इसलिए, मीम्स के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि ये मिडिल क्लास जोड़ो यात्रा लोगों को ज्यादा जोड़ रही है।

कैसे दूढ़ बजट में अपना फायदा?

आम बजट 2024-25 में लगभग हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। खासतौर से गरीबों और महिलाओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। देरों घोषणाएं होने के बाद सोशल मीडिया पर ये मीम्स शेयर हो रहा है। हर वर्ग अपना अपना फायदा बजट में ढूँढ रहा है। शायद कुछ इसी तरह के संकेत वाला यह मीम्स शेयर हुआ है।



➤ बजट पर एक मीम्स ऐसा भी जिसे देखने पर हंसी आना स्वाभाविक है...



➤ किसको क्या मिला 'ब्रो'... शायद यह मीम्स कुछ इसी तरह का संकेत है



➤ बजट से मिलने वाली राहत का उत्साह, कहा-तेरी लीला अपरंपार



हास्य कवियों के श्रीमुख से...

वित्त मंत्री तो घोषणाएं करके चल देती हैं...



महेश दुबे
हास्य कवि, मुंबई

जैसे ही नया बजट आया जोरदार हम सूखे पते की तरह कांपने लगे सरकार यह बजट हमें हर बार सताता है इस बजट से हमारा छतरी का नाता है बजट का गणित हमें लगता है गैजट्स इससे बिगड़ जाता है हमारे बैंक का बैलेंस वाहन सस्ते हुए तो बच्चों की फीज बाढ़क लेने को अड़ जाती है और सोना सस्ता हुआ तो पत्नी राशन पानी लेकर सिर पर चढ़ जाती है वित्तमंत्री तो घोषणाएं करके चल देती हैं इधर परिवार के लोग हमें डिमांड और सप्लाई की चक्की में मसल देते हैं।

बैठे-ठाले सूझ रहा... किसको यह हल्ला

उनकी चाबी, उनके ताले सस्ता कपड़ा, मुफ्त घरौंदा, फ्री में गल्ला बैठे - ठाले सूझ रहा, यह किसको हल्ला आज करोड़ों बेघर, दिखते हैं घरवाले उनकी छत है, उनकी चाबी, उनके ताले कोस रहा है सक्रियता को कौन निठल्ला बैठे - ठाले सूझ रहा, यह किसको हल्ला कृषकों को खुशहाल करेगी फसल योजना इसमें भी दुर्जन चाहेंगे कमी योजना कर्तव्यों से झाड़ेंगे... सब अपना पल्ला

बैठे-ठाले सूझ रहा, यह किसको हल्ला अब तो बिजली भी घर-घर को मुफ्त मिलेगी गुरझाए हर चेहरे पर मुस्कान खिलेगी दुष्ट लोग इस पर भी, अब जाएं गे झल्ला बैठे - ठाले सूझ रहा, यह किसको हल्ला निर्धन की अंगुली में क्यों है स्वर्ण अंगूठी लोकतंत्र की कायम कैसे प्रथा अनूठी भ्रष्टों की अंगुली से निकल गया है छल्ला बैठे - ठाले सूझ रहा, किसको यह हल्ला



विनेश प्रसाद
गीतकार, मोपाल

ऐसी दरकार तुम्हई से है

ये बजट की चहक फुलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्हई से है दीदी अपनी लखपत होंगी निर्धन की अपनी छत होगी अब राम राज्य का दौर चले ऐसी दरकार तुम्हई से है



सुदीप भोला
हास्य कवि, मुंबई

चिंतन

समावेशी विकास को गति देने वाला बजट

अंतरिम बजट के चलते पहले से ही जैसी उम्मीद थी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसी भी प्रकार के लोकलुभावन एलानों से परहेज किया। आयकर स्लैब को यथावत रखा गया है। कॉरपोरेट टैक्स में राहत दी गई है, पेंडिंग टैक्स 25 हजार व 10 हजार तक माफ किया गया है। अमृतकाल के इस दूसरे बजट में समावेशी विकास, सबके विश्वास और विकसित भारत विजन की अंतर्दृष्टि प्रस्तुत की गई है। इस बजट में अर्थव्यवस्था को दीर्घकालीन मजबूती देने का रोडमैप है। सड़क, रेल, एयरपोर्ट, सोलर व इलेक्ट्रिक एनर्जी, शोध व अनुसंधान, रक्षा तकनीक, ब्लू इकोनॉमी व डिजिटल आदि भविष्य की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की योजना पेश की गई है। यह बजट ग्रोथ औरिएटड है, इसमें मैक्रो व माइक्रो दोनों प्रबंधन हैं। वित्त मंत्री ने सरकार के फोकस वर्ग ज्ञान (गरीब, युवा, अन्नदाता व नारीशक्ति) पर अंतरिम बजट को केंद्रित किया है। इस बजट में मध्यम वर्ग का खास ध्यान रखा गया है। मध्यम वर्ग के लिए पहली बार अलग से आवास योजना शुरू करने की बात कही गई है। 2 करोड़ नए घर प्रधानमंत्री योजना के तहत बनाए जाएंगे। आशा वर्कर्स व आंगनबाड़ी में कार्यरत महिलाओं को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया गया है। सूर्योदय योजना के तहत एक करोड़ घरों में 300 यूनिट सोलर बिजली मुफ्त दी जाएगी। इससे बिजली आपूर्ति क्षेत्र में क्रांति आएगी। लखपति दीदी योजना के तहत 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी। ज्ञान, आशा व आंगनबाड़ी वर्कर्स व मध्यवर्ग को लक्षित करने का मतलब एक बड़े वोटबैंक को साधना है। मोदी सरकार जबसे सत्ता में आई है, क्लास इंजीनियरिंग को लाभ देकर नया जनाधार तैयार किया है। इस बजट में भी क्लास वोटबैंक को लुभाने की बारीकी छिपी हुई है। अंतरिम बजट में गरीबी रेखा से बाहर आए नियो मिडिल क्लास की आर्थिक समृद्धि बनाए रखने के लिए कई योजनाओं को रोलआउट किया गया है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में युद्ध और संघर्षों के कारण वैश्विक स्थिति अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण है, ऐसे भारत के सामने अपनी ग्रोथ को बरकरार रखने की महती चुनौती है। बजट में इस चुनौती से पार पाने की कोशिश है। 40,000 बेगियों को वंदे भारत स्टैंडर्ड में बदला जाएगा, 3 नए रेल कोरिडोर बनेंगे। उड़ान स्कीम के तहत नए एयरपोर्ट बनेंगे, मौजूदा एयरपोर्ट का विस्तार होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बजट 11.1 फीसदी बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये किया गया है। रक्षा बजट के लिए सबसे ज्यादा 6.2 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल से 3.4 फीसदी ज्यादा है। मत्स्य संपदा योजना को बढ़ावा दिया जाएगा, इससे 55 लाख नए रोजगार मिलेंगे। टेक-सेवी यूथ के लिए एक लाख करोड़ रुपये का कोष बनाया जाएगा, 50 साल तक ब्याज नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने भविष्य की वैकल्पिक ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक, सोलर व ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र को बढ़ावा देने का संकल्प दोहराया है। इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए 6,585 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य हासिल करना है। बजट में एफडीआई और जीडीपी को नए सिरे से परिभाषित किया गया है। एफडीआई यानी फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया व जीडीपी यानी गवर्नेंस डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। भारत आत्मनिर्भर व विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लिए संकल्पित है, इसलिए कृषि से लेकर उद्योग तक, कामगार से लेकर सेवा क्षेत्र तक सभी क्षेत्र के विकास पर ध्यान देना जरूरी है। सरकार बजट दर बजट यह प्रयास कर रही है, इस अंतरिम बजट में भी इसकी झलक है। राजकोषीय संतुलन का ध्यान रखा है। लक्षद्वीप सहित देश के पर्यटन स्थलों का विकास होगा। राज्यों के विकास को गति देने के लिए 50 वर्षीय दीर्घकालीन सस्ते ऋण देने के लिए 75 हजार करोड़ रुपये का कोष बनाया गया है। अमृतकाल के लिए सरकार ने ऐसी आर्थिक नीतियों को अपनाया है, जो टिकाऊ विकास, सभी के लिए अवसरों, क्षमता विकास पर केंद्रित है। सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के साथ आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ा रही है।

अंतरिम बजट आर.के. सिन्हा

दशकों बाद बजट में रक्षा क्षेत्र के साथ हुआ न्याय

भारत ने एक बार फिर से शत्रुओं को साफ संकेत और सख्त संदेश दे दिया कि वह अपनी सरहदों की निगाहबानी करने में कभी भी पीछे नहीं रहेगा। भारत अपने रक्षा क्षेत्र को निरंतर मजबूत करता रहेगा। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के अंतरिम बजट को देश के सामने पेश किया। उन्होंने बजट प्रस्तावों में रक्षा क्षेत्र के लिए पिछले वित्त साल की तुलना में 11.1 फीसद अधिक धन की व्यवस्था की। यह राशि देश के जीडीपी के कुल 3.4 फीसद होगी।यह एक स्पष्ट और सख्त संदेश है कि चीन और पाकिस्तान जैसे दो घोषित शत्रुओं के साथ भारत कभी भी अपनी सीमाओं की रखवाली करने में कमजोर रहने वाला नहीं है। रक्षा क्षेत्र को लेकर सबसे अच्छी बात यह हो रही है कि भारत रक्षा उत्पादन में आत्म निर्भर बनने का संकल्प ले चुका है। नरेन्द्र मोदी के केन्द्र सरकार पर 2014 में सत्तासीन होने के बाद सरकार की कोशिश रही है कि हम अपनी रक्षा जरूरतों का उत्पादन खुद करें। भारत सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के अनुरूप और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए,सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई नीतिगत पहल की हैं और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और स्टार्ट-अप सहित भारतीय उद्योग द्वारा रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन, विकास और निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सुधार लाए हैं, जिससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है। एक सुखद बात यह भी है कि टाटा, लार्सन एड टुब्रो, महिन्द्रा और ज़िंदल जैसे मशहूर उद्योग समूह रक्षा उत्पादन में निवेश कर रहे हैं। टाटा समूह रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाने की तैयार कर चुका है। टाटा मोटर्स, टाटा पावर और टाटा एडवॉंस्ड मैटीरियल्स रक्षा उत्पादन के काम में खासतौर पर बहुत एक्टिव हैं। भारत के सालाना लघुमग दो लाख करोड़ के रक्षा बाजार को नब्बजा करने में टाटा समूह एक बड़े प्लेयर के रूप में ऊभर रहा है। भारत को अपने दुश्मनों से पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए देश को इस क्षेत्र में हर हालत में एक स्तर तक तो आत्म निर्भर होना ही होगा। इस लिहाज से देश के निजी क्षेत्र पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। दरअसल स्टॉकहोम इंटरनेशनल ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में बताया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है।रिपोर्ट के अनुसार, साल 2013-17 और 2018-22 के बीच भारत की हथियार खरीद में 11 प्रतिशत की कमी आई है, इसके बावजूद भारत हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश बना हुआ है। बीते पांच सालों में दुनिया में जितने हथियार खरीदे गए, उनमें से 11 प्रतिशत अकेले भारत ने खरीदे। सऊदी अरब (9.6 फीसदी) खरीद के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं इनके बाद कतर (6.4%), ऑस्ट्रेलिया (4.7%) और चीन (4.7%) का नंबर आता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का निर्यातक इसलिए बना क्योंकि वह चीन और पाकिस्तान जैसे देशों का पड़ोसी है। चीन और पाकिस्तान भारत को किसी ना किसी तरह से क्षति पहुंचाने की फिराक में रहते हैं। इसलिए भारत के पास अपने रक्षा बजट को लगातार बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सोच के चलते ही अपने अंतरिम बजट में रक्षा क्षेत्र को दिल खोल धन दिया। भारत की तफ से पूरे विश्व को यह संदेश जाते रहना चाहिए कि हम रक्षा क्षेत्र को मजबूत करते हुए अपने अन्य क्षेत्रों की भी अनदेखी नहीं करेंगे। यह भी गौरतलब है कि भारत रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बनने जा रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले नौ साल में देश में रक्षा निर्यात में 23 गुणा की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल 100 से अधिक कंपनियों के जरिए देश में रक्षा क्षेत्र से जुड़ा सामान का उत्पादन हो रहा है। इन्हें 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत बनाया जा रहा है।

(लेखक पूर्ण सांखर्ग है, ये उनके अपने विचार हैं।)

अंतरिम बजट आलोक पुराणिक

अंतरिम बजट 2024–25 के पूरे बजट भाषण में वित्तमंत्री की ये 2 पंक्तियां सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिनका आशय यह है कि आयकरदाताओं के कर दायित्व में कोई बदलाव नहीं है, वो जितना कर पहले दे रहे थे, वो ही कर उन्हें अब भी देना होगा। राहत अब भी उम्मीद है जो शायद 2024–2025 के पूरे बजट में पूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। पूरे बजट के लिए लोकसभा चुनावों के बाद की सरकार का इंतजार करना होगा। जिस आत्मविश्वास से बजट में आने वाले कई सालों की बात गई है, उसे देखकर लगता है कि केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आश्चस्त हैं कि अगली कई सरकारें उन्हीं के गठबंधन की होंगी। आत्मविश्वास तो भविष्य पर निर्भर है। कुल मिलाकर कर आयकर आदि को लेकर हालात जस के तस हैं, पर सरकार के तेवर चुनावी हैं और अंतरिम बजट के मौके का बखूबी इस्तेमाल किया सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए। यह भी कहा जा सकता है कि सरकार ने आयकरदाताओं की जेब से और कर नहीं खींचा है, तो इसे सकारात्मक ही मानना चाहिए। सरकार अगर आपसे कुछ नया नहीं ले रही है, तो समझिये कि आपको दे ही रही है। यह एक दृष्टिकोण है स्थितियों को समझने का। अंतरिम बजट के मुताबिक 23-24 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.8 प्रतिशत रहेगा। 24-25 में यह राजकोषीय घाटा 5.1 प्रतिशत रहने के अनुमान हैं। 25-26 में यह राजकोषीय घाटा 4.5 प्रतिशत रहने के अनुमान है। लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है, पर आकर्षक है।

भारत और मालदीव के बीच हाल में एक विवाद खड़ा हो गया था। मालदीव सरकार के कुछ महत्वपूर्ण लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर आपत्ति जताई। अब अंतरिम बजट में पर्यटन विकास की बात कही गई हैं। पर्यटन अपने आप में महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उस पर जल्द से जल्द काम होना चाहिए, पर यह सिर्फ केंद्र सरकार की इच्छा का मसला नहीं है। राज्य सरकारों का सहयोग भी इसमें जरूरी है। लक्षद्वीप का विकास होगा।

प्रति व्यक्ति आय करीब 9 सालों में दोगुनी होकर 1 लाख 97 हजार रुपये हो गई है। नौ सालों में अर्थव्यवस्था विश्व में दसवें नंबर से उठकर पांचवें नम्बर पर आ गई

स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ शौचालय निर्मित हुए। उज्ज्वला योजना में करीब 9.6 करोड़ गैस

हर युग में प्रासंगिक ‘महादेव’

कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं आदियोगी शिव का प्रशंसक हूं। प्रशंसक होने का अर्थ है कि उसकी भावनाओं से जुड़ जाना। मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं शिव को महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूं, क्योंकि उनका योगदान काल के परे है। इसलिए वे सदा प्रासंगिक हैं। किसी भी पीढ़ी में किसी इंसान की प्रशस्ति उस योगदान के लिए की जाती है, जो उसने उस पीढ़ी या आने वाली पीढ़ियों के लिए किया है। इस धरती पर कई ऐसे लोग आए हैं, जिन्होंने दूसरों के जीवन में योगदान किया है। जो उस समय की जरूरत के अनुसार था, वह उसे लेकर आया। गौतम बुद्ध के समय समाज कर्मकांडों में लिपटा हुआ था। जब उन्होंने बिना किसी कर्मकांड के आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू की तो वह लोकप्रिय हो गए। अगर समाज में कर्मकांड नहीं होते, तो वह इतने महत्वपूर्ण नहीं होते। कृष्ण बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन फिर भी, यदि पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध नहीं होता, तो वह सिर्फ अपने आसपास की जगहों पर प्रभावशाली होते। आदियोगी या शिव का महत्व यही है कि उनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई टकराव नहीं हुआ। उन्होंने मानव चेतना को इस प्रकार से विकसित करने के साधन और तरीके दिए कि वे हर युग में प्रासंगिक रहें। हमने उन्हें महादेव की उपाधि दी, क्योंकि उनके योगदान के पीछे की बुद्धि, दृष्टि और ज्ञान अद्भुत है।

विकास के पक्के इरादों का बजट

विश्लेषण डॉ. जयंतीलाल भंडारीवरिष्ठ अर्थशास्त्री

यकीनन वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट आम आदमी की खुशहाली और देश के तेजी से विकास के दावों, वादों, इशंदों और वित्तीय अनुशासन का आदर्श गुलदस्ता है। इस बजट में गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए जो अहम घोषणाएं की गई हैं, उनसे विकास और आर्थिक कल्याण का नया अध्याय लिखा जा सकेगा। साथ ही यह अंतरिम बजट विकास का ऐसा रोडमैप भी है, जिससे 2047 तक दुनिया का विकसित देश बनने की डगर पर आगे बढ़ता दिखाई दे सकेगा।

यदि हम वित्तमंत्री सीतारमण के द्वारा अंतरिम बजट में प्रस्तुत किए गए वर्ष 2023-24 के आय-व्यय से संशोधित अनुमान की स्थिति देखें तो पाते हैं कि उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 27.56 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से कर प्राप्ति 23.24 लाख करोड़ रुपये है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़ रुपये है। 30.03 लाख करोड़ की राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान से अधिक रहने की उम्मीद है, जो अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास दर और इसके औपचारीकरण को दर्शाता है। इसी तरह वर्ष 2024-25 के बजट के तहत उधारी से इतर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 30.80 लाख करोड़ और 47.66 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। कर प्राप्तियां 26.02 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।

निःसंदेह देश की आजादी के बाद से अब तक जितने अंतरिम बजट आए हैं, उन सभी बजटों में वित्तीय अनुशासन के मद्देनजर वित्तमंत्री सीतारमण का यह बजट चमकता दिखाई दे रहा है। खासतौर वर्ष 2000 के बाद प्रस्तुत हुए तीन अंतरिम बजटों में लोक लुभावन घोषणाएं की गई थी और कर उपायों की अनदेखी की गई थी। साथ ही पिछले लोकसभा चुनाव के पहले कार्यवाहक वित्तमंत्री पीयूष गोयल के वर्ष 2019-2020 के अंतरिम बजट में किसान

राहत के लिए पिव्चर अभी बाकी है

निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट 2024-25 के भाषण में अपनी सरकार की करीब 10 साल की उपलब्धियां गिनवाईं और कोई नया बड़ा प्रस्ताव पेश नहीं किया। यूं अगर वह चाहती तो थोड़ी बहुत राहत कर आदि के मामले में खासकर मध्य वर्गीय करदाताओं को दे सकती थीं। पूरे बजट भाषण में वित्तमंत्री की ये 2 पंक्तियां सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिनका आशय यह है कि आयकरदाताओं के कर दायित्व में कोई बदलाव नहीं है, वो जितना कर पहले दे रहे थे, वो ही कर उन्हें अब भी देना होगा। राहत की अब भी उम्मीद है जो शायद 2024-2025 के पूर्ण बजट में पूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। पूरे बजट के लिए लोकसभा चुनावों के बाद की सरकार का इंतजार करना होगा।जिस आत्मविश्वास से बजट में आने वाले कई सालों की बात गई है, उसे देखकर लगता है कि केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आश्चस्त हैं कि अगली कई सरकारें उन्हीं के गठबंधन की होंगी। आत्मविश्वास तो भविष्य पर निर्भर है। कुल मिलाकर कर आयकर आदि को लेकर हालात जस के तस हैं, पर सरकार के तेवर चुनावी हैं और अंतरिम बजट के मौके का बखूबी इस्तेमाल किया सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए। यह भी कहा जा सकता है कि सरकार ने आयकरदाताओं की जेब से और कर नहीं खींचा है, तो इसे सकारात्मक ही मानना चाहिए। सरकार अगर आपसे कुछ नया नहीं ले रही है, तो समझिये कि आपको दे ही रही है। यह एक दृष्टिकोण है स्थितियों को समझने का। अंतरिम बजट के मुताबिक 23-24 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.8 प्रतिशत रहेगा। 24-25 में यह राजकोषीय घाटा 5.1 प्रतिशत रहने के अनुमान हैं। 25-26 में यह राजकोषीय घाटा 4.5 प्रतिशत रहने के अनुमान है। लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है, पर आकर्षक है।



सकती है। पर एक महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की जाएगी, इसे 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपये किया गया है, जो जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है, यह निश्चय ही बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। पूंजीगत व्यय से आशय ऐसे व्यय से है, जिसमें पुल, सड़क आदि बनते हैं, अर्थव्यवस्था में कंस्ट्रक्शन होता है, तो अर्थव्यवस्था में चौतरफा सकारात्मक असर होता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन चाहे जैसे हो, अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण और सकारात्मक ही माना जाना चाहिए।

बजट की राजनीति होती है। बिना राजनीति के बजट हो नहीं सकता। पीएम मोदी ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ-युवा, गरीब, महिला और किसान, को सशक्त करेगा। बिहार के जाति सर्वेक्षण के बाद जाति की राजनीति पर नये सिरे से चर्चा शुरू हो गई थी। इसके जवाब में प्रधानमंत्री का आशय है कि जातियां चार हैं-युवा, गरीब, महिला और किसान, इन्हे ताकत दी जाए तो समाज सशक्त होता है। बजट में सरकार का दावा रहा कि महंगाई नरम स्तर पर रही है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया के मुताबिक चार प्रतिशत की महंगाई दर से ऊपर या नीचे, दो प्रतिशत बिंदुओं की हेरफेर तो सहनीय है। दिसंबर

कनेक्शन दिए गए। 47.8 करोड़ पीएम जनधन बैंक खाते खोले गए। 11 करोड़ 40 लाख किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपये का ट्रांसफर हुआ पीएम किसान सम्मान निधि में। ये कुछ उपलब्धियां गिनवाई हैं।

यानी अंतरिम बजट 2024-25 के जो मुख्य बिंदु बताए गए हैं, वो दरअसल चुनाव बिंदु हैं और चुनाव के बाद असल में बजट के असली प्रावधान पेश किए जाएंगे। इस तरह से अंतरिम बजट को हद से हद एक घोषणापत्र ही कहा जा सकता है, घोषणा बाद में बदल

सकती है। पर एक महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की जाएगी, इसे 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपये किया गया है, जो जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है, यह निश्चय ही बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। पूंजीगत व्यय से आशय ऐसे व्यय से है, जिसमें पुल, सड़क आदि बनते हैं, अर्थव्यवस्था में कंस्ट्रक्शन होता है, तो अर्थव्यवस्था में चौतरफा सकारात्मक असर होता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन चाहे जैसे हो, अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण और सकारात्मक ही माना जाना चाहिए।

बजट की राजनीति होती है। बिना राजनीति के बजट हो नहीं सकता। पीएम मोदी ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ-युवा, गरीब, महिला और किसान, को सशक्त करेगा। बिहार के जाति सर्वेक्षण के बाद जाति की राजनीति पर नये सिरे से चर्चा शुरू हो गई थी। इसके जवाब में प्रधानमंत्री का आशय है कि जातियां चार हैं-युवा, गरीब, महिला और किसान, इन्हे ताकत दी जाए तो समाज सशक्त होता है। बजट में सरकार का दावा रहा कि महंगाई नरम स्तर पर रही है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया के मुताबिक चार प्रतिशत की महंगाई दर से ऊपर या नीचे, दो प्रतिशत बिंदुओं की हेरफेर तो सहनीय है। दिसंबर

कनेक्शन दिए गए। 47.8 करोड़ पीएम जनधन बैंक खाते खोले गए। 11 करोड़ 40 लाख किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपये का ट्रांसफर हुआ पीएम किसान सम्मान निधि में। ये कुछ उपलब्धियां गिनवाई हैं।

यानी अंतरिम बजट 2024-25 के जो मुख्य बिंदु बताए गए हैं, वो दरअसल चुनाव बिंदु हैं और चुनाव के बाद असल में बजट के असली प्रावधान पेश किए जाएंगे। इस तरह से अंतरिम बजट को हद से हद एक घोषणापत्र ही कहा जा सकता है, घोषणा बाद में बदल

सकती है। पर एक महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की जाएगी, इसे 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपये किया गया है, जो जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है, यह निश्चय ही बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। पूंजीगत व्यय से आशय ऐसे व्यय से है, जिसमें पुल, सड़क आदि बनते हैं, अर्थव्यवस्था में कंस्ट्रक्शन होता है, तो अर्थव्यवस्था में चौतरफा सकारात्मक असर होता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन चाहे जैसे हो, अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण और सकारात्मक ही माना जाना चाहिए।

बजट की राजनीति होती है। बिना राजनीति के बजट हो नहीं सकता। पीएम मोदी ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ-युवा, गरीब, महिला और किसान, को सशक्त करेगा। बिहार के जाति सर्वेक्षण के बाद जाति की राजनीति पर नये सिरे से चर्चा शुरू हो गई थी। इसके जवाब में प्रधानमंत्री का आशय है कि जातियां चार हैं-युवा, गरीब, महिला और किसान, इन्हे ताकत दी जाए तो समाज सशक्त होता है। बजट में सरकार का दावा रहा कि महंगाई नरम स्तर पर रही है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया के मुताबिक चार प्रतिशत की महंगाई दर से ऊपर या नीचे, दो प्रतिशत बिंदुओं की हेरफेर तो सहनीय है। दिसंबर

कनेक्शन दिए गए। 47.8 करोड़ पीएम जनधन बैंक खाते खोले गए। 11 करोड़ 40 लाख किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपये का ट्रांसफर हुआ पीएम किसान सम्मान निधि में। ये कुछ उपलब्धियां गिनवाई हैं।

यानी अंतरिम बजट 2024-25 के जो मुख्य बिंदु बताए गए हैं, वो दरअसल चुनाव बिंदु हैं और चुनाव के बाद असल में बजट के असली प्रावधान पेश किए जाएंगे। इस तरह से अंतरिम बजट को हद से हद एक घोषणापत्र ही कहा जा सकता है, घोषणा बाद में बदल

सकती है। पर एक महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की जाएगी, इसे 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपये किया गया है, जो जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है, यह निश्चय ही बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। पूंजीगत व्यय से आशय ऐसे व्यय से है, जिसमें पुल, सड़क आदि बनते हैं, अर्थव्यवस्था में कंस्ट्रक्शन होता है, तो अर्थव्यवस्था में चौतरफा सकारात्मक असर होता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन चाहे जैसे हो, अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण और सकारात्मक ही माना जाना चाहिए।

बजट की राजनीति होती है। बिना राजनीति के बजट हो नहीं सकता। पीएम मोदी ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ-युवा, गरीब, महिला और किसान, को सशक्त करेगा। बिहार के जाति सर्वेक्षण के बाद जाति की राजनीति पर नये सिरे से चर्चा शुरू हो गई थी। इसके जवाब में प्रधानमंत्री का आशय है कि जातियां चार हैं-युवा, गरीब, महिला और किसान, इन्हे ताकत दी जाए तो समाज सशक्त होता है। बजट में सरकार का दावा रहा कि महंगाई नरम स्तर पर रही है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया के मुताबिक चार प्रतिशत की महंगाई दर से ऊपर या नीचे, दो प्रतिशत बिंदुओं की हेरफेर तो सहनीय है। दिसंबर

कनेक्शन दिए गए। 47.8 करोड़ पीएम जनधन बैंक खाते खोले गए। 11 करोड़ 40 लाख किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपये का ट्रांसफर हुआ पीएम किसान सम्मान निधि में। ये कुछ उपलब्धियां गिनवाई हैं।

यानी अंतरिम बजट 2024-25 के जो मुख्य बिंदु बताए गए हैं, वो दरअसल चुनाव बिंदु हैं और चुनाव के बाद असल में बजट के असली प्रावधान पेश किए जाएंगे। इस तरह से अंतरिम बजट को हद से हद एक घोषणापत्र ही कहा जा सकता है, घोषणा बाद में बदल

सकती है। पर एक महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की जाएगी, इसे 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपये किया गया है, जो जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है, यह निश्चय ही बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। पूंजीगत व्यय से आशय ऐसे व्यय से है, जिसमें पुल, सड़क आदि बनते हैं, अर्थव्यवस्था में कंस्ट्रक्शन होता है, तो अर्थव्यवस्था में चौतरफा सकारात्मक असर होता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन चाहे जैसे हो, अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण और सकारात्मक ही माना जाना चाहिए।

बजट की राजनीति होती है। बिना राजनीति के बजट हो नहीं सकता। पीएम मोदी ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ-युवा, गरीब, महिला और किसान, को सशक्त करेगा। बिहार के जाति सर्वेक्षण के बाद जाति की राजनीति पर नये सिरे से चर्चा शुरू हो गई थी। इसके जवाब में प्रधानमंत्री का आशय है कि जातियां चार हैं-युवा, गरीब, महिला और किसान, इन्हे ताकत दी जाए तो समाज सशक्त होता है। बजट में सरकार का दावा रहा कि महंगाई नरम स्तर पर रही है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया के मुताबिक चार प्रतिशत की महंगाई दर से ऊपर या नीचे, दो प्रतिशत बिंदुओं की हेरफेर तो सहनीय है। दिसंबर

कनेक्शन दिए गए। 47.8 करोड़ पीएम जनधन बैंक खाते खोले गए। 11 करोड़ 40 लाख किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपये का ट्रांसफर हुआ पीएम किसान सम्मान निधि में। ये कुछ उपलब्धियां गिनवाई हैं।

यानी अंतरिम बजट 2024-25 के जो मुख्य बिंदु बताए गए हैं, वो दरअसल चुनाव बिंदु हैं और चुनाव के बाद असल में बजट के असली प्रावधान पेश किए जाएंगे। इस तरह से अंतरिम बजट को हद से हद एक घोषणापत्र ही कहा जा सकता है, घोषणा बाद में बदल

सकती है। पर एक महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की जाएगी, इसे 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपये किया गया है, जो जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है, यह निश्चय ही बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। पूंजीगत व्यय से आशय ऐसे व्यय से है, जिसमें पुल, सड़क आदि बनते हैं, अर्थव्यवस्था में कंस्ट्रक्शन होता है, तो अर्थव्यवस्था में चौतरफा सकारात्मक असर होता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन चाहे जैसे हो, अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण और सकारात्मक ही माना जाना चाहिए।

बजट की राजनीति होती है। बिना राजनीति के बजट हो नहीं सकता। पीएम मोदी ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ-युवा, गरीब, महिला और किसान, को सशक्त करेगा। बिहार के जाति सर्वेक्षण के बाद जाति की राजनीति पर नये सिरे से चर्चा शुरू हो गई थी। इसके जवाब में प्रधानमंत्री का आशय है कि जातियां चार हैं-युवा, गरीब, महिला और किसान, इन्हे ताकत दी जाए तो समाज सशक्त होता है। बजट में सरकार का दावा रहा कि महंगाई नरम स्तर पर रही है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया के मुताबिक चार प्रतिशत की महंगाई दर से ऊपर या नीचे, दो प्रतिशत बिंदुओं की हेरफेर तो सहनीय है। दिसंबर

कनेक्शन दिए गए। 47.8 करोड़ पीएम जनधन बैंक खाते खोले गए। 11 करोड़ 40 लाख किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपये का ट्रांसफर हुआ पीएम किसान सम्मान निधि में। ये कुछ उपलब्धियां गिनवाई हैं।

यानी अंतरिम बजट 2024-25 के जो मुख्य बिंदु बताए गए हैं, वो दरअसल चुनाव बिंदु हैं और चुनाव के बाद असल में बजट के असली प्रावधान पेश किए जाएंगे। इस तरह से अंतरिम बजट को हद से हद एक घोषणापत्र ही कहा जा सकता है, घोषणा बाद में बदल

सकती है। पर एक महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की जाएगी, इसे 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपये किया गया है, जो जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है, यह निश्चय ही बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। पूंजीगत व्यय से आशय ऐसे व्यय से है, जिसमें पुल, सड़क आदि बनते हैं, अर्थव्यवस्था में कंस्ट्रक्शन होता है, तो अर्थव्यवस्था में चौतरफा सकारात्मक असर होता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन चाहे जैसे हो, अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण और सकारात्मक ही माना जाना चाहिए।

बजट की राजनीति होती है। बिना राजनीति के बजट हो नहीं सकता। पीएम मोदी ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ-युवा, गरीब, महिला और किसान, को सशक्त करेगा। बिहार के जाति सर्वेक्षण के बाद जाति की राजनीति पर नये सिरे से चर्चा शुरू हो गई थी। इसके जवाब में प्रधानमंत्री का आशय है कि जातियां चार हैं-युवा, गरीब, महिला और किसान, इन्हे ताकत दी जाए तो समाज सशक्त होता है। बजट में सरकार का दावा रहा कि महंगाई नरम स्तर पर रही है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया के मुताबिक चार प्रतिशत की महंगाई दर से ऊपर या नीचे, दो प्रतिशत बिंदुओं की हेरफेर तो सहनीय है। दिसंबर

कनेक्शन दिए गए। 47.8 करोड़ पीएम जनधन बैंक खाते खोले गए। 11 करोड़ 40 लाख किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपये का ट्रांसफर हुआ पीएम किसान सम्मान निधि में। ये कुछ उपलब्धियां गिनवाई हैं।

यानी अंतरिम बजट 2024-25 के जो मुख्य बिंदु बताए गए हैं, वो दरअसल चुनाव बिंदु हैं और चुनाव के बाद असल में बजट के असली प्रावधान पेश किए जाएंगे। इस तरह से अंतरिम बजट को हद से हद एक घोषणापत्र ही कहा जा सकता है, घोषणा बाद में बदल

सकती है। पर एक महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की जाएगी, इसे 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपये किया गया है, जो जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है, यह निश्चय ही बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। पूंजीगत व्यय से आशय ऐसे व्यय से है, जिसमें पुल, सड़क आदि बनते हैं, अर्थव्यवस्था में कंस्ट्रक्शन होता है, तो अर्थव्यवस्था में चौतरफा सकारात्मक असर होता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन चाहे जैसे हो, अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण और सकारात्मक ही माना जाना चाहिए।

बजट की राजनीति होती है। बिना राजनीति के बजट हो नहीं सकता। पीएम मोदी ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ-युवा, गरीब, महिला और किसान, को सशक्त करेगा। बिहार के जाति सर्वेक्षण के बाद जाति की राजनीति पर नये सिरे से चर्चा शुरू हो गई थी। इसके जवाब में प्रधानमंत्री का आशय है कि जातियां चार हैं-युवा, गरीब, महिला और किसान, इन्हे ताकत दी जाए तो समाज सशक्त होता है। बजट में सरकार का दावा रहा कि महंगाई नरम स्तर पर रही है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया के मुताबिक चार प्रतिशत की महंगाई दर से ऊपर या नीचे, दो प्रतिशत बिंदुओं की हेरफेर तो सहनीय है। दिसंबर

कनेक्शन दिए गए। 47.8 करोड़ पीएम जनधन बैंक खाते खोले गए। 11 करोड़ 40 लाख किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपये का ट्रांसफर हुआ पीएम किसान सम्मान निधि में। ये कुछ उपलब्धियां गिनवाई हैं।

यानी अंतरिम बजट 2024-25 के जो मुख्य बिंदु बताए गए हैं, वो दरअसल चुनाव बिंदु हैं और चुनाव के बाद असल में बजट के असली प्रावधान पेश किए जाएंगे। इस तरह से अंतरिम बजट को हद से हद एक घोषणापत्र ही कहा जा सकता है, घोषणा बाद में बदल

सकती है। पर एक महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की जाएगी, इसे 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपये किया गया है, जो जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है, यह निश्चय ही बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। पूंजीगत व्यय से आशय ऐसे व्यय से है, जिसमें पुल, सड़क आदि बनते हैं, अर्थव्यवस्था में कंस्ट्रक्शन होता है, तो अर्थव्यवस्था में चौतरफा सकार

कुछ बच्चे एग्जाम के दिनों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। वे एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर घबराए रहते हैं। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा है तो हम तुम्हें एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स दे रहे हैं। इन्हें अमल में लाकर तुम जब प्रिपरेशन करोगे, तुम्हें कोई स्ट्रेस नहीं होगा, तुम बहुत आसानी से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकोगे।

अंग्रेजी शब्द-जाल



बच्चो, नीचे दिए गए इस अंग्रेजी शब्द-जाल में पढ़ाई से जुड़े 11 शब्द छिपे हैं। जल्दी से इन्हें खोजकर बताओ।



1. पढ़ाई के लिए एक चीज

2. एक देश का मानचित्र

3. एक चीज जो हम अपने साथ ले जाते हैं

4. एक चीज जो हम अपने साथ ले जाते हैं

5. एक चीज जो हम अपने साथ ले जाते हैं

6. एक चीज जो हम अपने साथ ले जाते हैं

7. एक चीज जो हम अपने साथ ले जाते हैं

8. एक चीज जो हम अपने साथ ले जाते हैं

9. एक चीज जो हम अपने साथ ले जाते हैं

10. एक चीज जो हम अपने साथ ले जाते हैं

11. एक चीज जो हम अपने साथ ले जाते हैं

1. पढ़ाई के लिए एक चीज

2. एक देश का मानचित्र

3. एक चीज जो हम अपने साथ ले जाते हैं

4. एक चीज जो हम अपने साथ ले जाते हैं

5. एक चीज जो हम अपने साथ ले जाते हैं

6. एक चीज जो हम अपने साथ ले जाते हैं

7. एक चीज जो हम अपने साथ ले जाते हैं

8. एक चीज जो हम अपने साथ ले जाते हैं

9. एक चीज जो हम अपने साथ ले जाते हैं

10. एक चीज जो हम अपने साथ ले जाते हैं

11. एक चीज जो हम अपने साथ ले जाते हैं

